

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1361/2011/झालावाड़

मैसर्स राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स,
भवानीमंडी, झालावाड़

...अपीलार्थी

बनाम

1. सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग
वृत्त, झालावाड़
2. उपायुक्त (अपील्स)
वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर
कैम्प कोटा

...प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम.एल.पाटोदी
अभिभाषक
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

....प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.09.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त अपील अपीलार्थी की ओर से उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 82 में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.05.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वृत्त झालावाड़ (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा धारा 24 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2010 द्वारा आरोपित मांग राशि रु 18,07,917/- को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यापारी की और आलोच्य अवधि वर्ष 2007-08 में कुल कर देयता 44,06,470/- बनती थी जिसमें से उसके द्वारा 32,49,662/- विभिन्न तिथियों में राजकोष में जमा करवाये गये और 11,56,808/- जमा नहीं करवाये गये जिसका कारण यह बताया गया कि 04-05 एवं 05-06 की रिफ्स ब्याज अनुदान की राशि विभाग से प्राप्त होनी थी। कर निर्धारण अधिकारी ने यह माना कि निर्धारित समय में कर देयता व रिफ्स से प्राप्त अनुदान दोनों पृथक-पृथक है इस अनुदान की राशि को कर देयता से जोड़ना न्यायोचित नहीं हैं इसलिये इस राशि को बकाया मानते हुये 61,228/- का ब्याज आरोपित किया गया। 31.03.2008 तक सम्मिलित राशि पर 3,90,872 का ब्याज एवं 37,59,750/- पर 01.04.09 से 09.09.08



लगातार.....2

2m

तक का 199,009/- ब्याज आरोपित किया गया। इस प्रकार कुल 6,51,109/- का ब्याज आरोपित किया गया। इस प्रकार कुल ब्याज 651109/-रु. एवं 11,56,808/- रु कुल 18,07,917/- रु. वसूल योग्य निर्धारित किये जिससे अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई। अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपील अस्वीकार की है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से कथन किया गया कि सहायक आयुक्त वृत्त झालावाड ने अपीलान्त के नाम ब्याज अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र 47,31,000/- का जारी किया था जिसके आधार पर अपीलान्त ने 11,56,808/- के ब्याज अनुदान को 07-08 के कर के पेटे समायोजित कर लिया। बाद में ब्याज अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र को संशोधित करते हुए 3,59,000/- का पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया जबकि अपीलान्त 11,56,808/- के कर को ब्याज अनुदान के पेटे समायोजित कर चुका था, इसलिये ब्याज अनुदान के पेटे समायोजित की गई राशि को स्वीकार किया जावे और आरोपित ब्याज समाप्त किया जावे।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी की कुल कर देयता 44,06,470/- बनती थी जिसमें से उसके द्वारा 32,49,662/- विभिन्न तिथियों में राजकोष में जमा करवाये गये और 11,56,808/- जमा नहीं करवाये गये। अपीलार्थी का इस संबंध में यह कथन है कि चूंकि वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 की रिप्स ब्याज की अनुदान की राशि विभाग से प्राप्त होनी थी तथा इसे कम करते हुये कर राशि जमा करवायी है। Tax payable के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 17(1) का अवलोकन करना समीचीन है जो निम्न प्रकार है :-

17. Tax payable by a dealer. - (1) Subject to the other provisions of this Act, the net tax payable by a registered dealer, other than the dealer covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, for a tax period shall be calculated as under: -

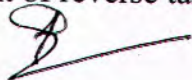
$$T = (O+R+P) - I$$

Where -

T is net tax payable;

O is amount of output tax;

R is amount of reverse tax;



2/11

लगातार.....3

P is the amount of tax payable under sub-section (2) of section 4; and
I is the amount of input tax.

(2) Where the net tax payable under sub-section (1) has a negative value, the same shall be first adjusted against any tax payable or amount outstanding under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) or under this Act or the repealed Act and the balance amount if any, shall be carried forward to the next tax period or periods. In case the dealer claims refund of the balance amount, if any, at the end of the year, the same shall be granted only after the end of the immediately succeeding year. However, the Commissioner after recording reasons for doing so may, by a general or specific order, direct to grant such refunds even earlier.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, where the sales are made on behalf of the principal registered under this Act by an agent also registered under this Act, such sales shall be deemed to be the sales of the principal and the agent shall render the accounts of such sales in the manner as may be prescribed.

(4) Every person whose registration is cancelled under this Act shall pay tax in the manner prescribed in respect of every taxable goods held in stock and capital goods on the date of such cancellation.

इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि देय योग्य कर 44,06,470/- रु था। अपीलार्थी ने 32,49,662/- रु. जमा करवा दिये परन्तु 11,56,808/- यह मानते हुये जमा नहीं कराये कि चूंकि उसे रिफ्स के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त होना है अतः यह राशि उसमें समायोजित हो जायेगी। इस खण्डपीठ की विनम्र राय के अनुसार रिफ्स के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त होना व अनुदान की मात्रा का निर्धारण सक्षम स्तर पर अलग से होता है तथा इसे सुनिश्चित मानकर कर देयता में से कम नहीं किया जा सकता। अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय है जो अधिकार के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी व्यवहारी ने प्राप्त होने वाले अनुदान की आशा में अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित कर जमा नहीं करवाया है जिससे जमा नहीं करवाये गये कर पर ब्याज की देयता बनती है।

8. जहा तक प्रकरण में अनुदान की गणना का बिन्दु है इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड, उमा पोलिमर्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक 24.11.2011 द्वारा यह अवधारित किया जा चुका है कि out put tax में से Input tax को घटाने के पश्चात् शेष राशि Tax payable है। इस प्रकार Tax payable राशि पर ही अनुदान देय है। इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अपील संख्या 1593 से 1603/2014 में श्री सीमेन्ट लि. ब्यावर बनाम सहायक आयुक्त में भी सम्माननीय पीठ ने इस अवधारणा के अनुसार अपील अस्वीकार की है। इस प्रकार निर्धारण अधिकारी ने विधिसम्मत रूप से अदेय कर व अदेय कर पर ब्याज आरोपित करते हुये वसूली निर्धारित की है तथा अपीलीय अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)

सदस्य

(नन्धूराम)

सदस्य